विचार-प्रवाह...फिल्म इंडस्ट्री में काफी गर्मागर्मी

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 28 जनवरी 2020

मौसम अधिकतम 16.0° न्यूनतम 9.0°

41155.12

2 सीएए विरोधी प्रदर्शन में घुसे पाक समर्थक | 7 टीम इंडिया बेरहम बनती जा रही है

संक्षिप्त समाचार

अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली में वोटिंग की तारीख पास आते-आते शाहीन बाग पर चुनावी तकरार तीखी होती जा रही है। बीजेपी ने सोमवार को शाहीन बाग प्रदर्शन के पीछे केजरीवाल सरकार और कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने इसके लिए अब बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि शाहीन बाग में बंद रास्ते की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।

सीएए प्रदर्शन के दौरान पीएफआई ने ट्रांसफर किए करोड़ों

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून 2019 कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के लिए 120 करोड़ रुपये का फंड मुहैया कराया था। जानकारी के अनुसार यह पैसा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल,वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत ए दवे और अब्दुल समद सहित कई नामचीन हस्तियों को ट्रांसफर किया गया। जबकि 1.65 करोड़ रुपये पीएफआइ कश्मीर को ट्रांसफर किए गए।

बोडो समझौते पर मोदी, शांति की नई सुबह आएगी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। बोडो समूहों के साथ सोमवार को हुए समझौते की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता शांति, सद्भाव और एकजुटता की नई सुबह लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सशस्त्र संघर्ष समूहों से जुड़े हुए थे, वे मुख्यधारा में शामिल होंगे और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे। पीएम ने कहा कि इस समझौते के बोडो लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे क्योंकि यह प्रमुख पक्षकारों को एक साथ एक प्रारूप में लेकर आएगा।

शाह ने बुझाई बोडो अलगाव की लौ

तृतीय असम समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के राज्यों से उग्रवाद के खात्मे का वादा करके सत्ता में आई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस दिशा में सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने असम समझौता 2020 पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया, जिसमें अब तक 2823 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 27 साल में यह तीसरा असम समझौता है।

सूत्रों के मुताबिक इस विवाद के जल्द समाधान के लिए मोदी सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी और अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद इसमें काफी

■बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने असम समझौते पर हस्ताक्षर किया

तेजी आई।

इस मौके पर गृह मंत्री ने ऐलान किया कि उग्रवादी गुट नैशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1550 कैडर 30 जनवरी को अपने 130 हथियार सौंप देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। शाह ने कहा कि इस समझौते के बाद अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बोडो लोगों से किए गए अपने सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद अब कोई अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा। साल 1987 में

ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने एक बार फिर से बोडोलैंड बनाए जाने की मांग की। यूनियन के नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने उस समय असम को 50-50 में बांटने की मांग की। दरअसल, यह विवाद असम आंदोलन (1979-85) का परिणाम था जो असम समझौते के बाद शुरू हुआ।

क्या है बोडो विवाद

करीब करीब 50 साल पहले असम के बोडो बहुल इलाकों में अलग राज्य बनाए जाने को लेकर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एनडीएफबी ने किया। यह विरोध इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967 के तहत एनडीएफबी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। बोडो उग्रवादियों पर हिंसा, जबरन उगाही और हत्या का आरोप है। 2823 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं।

जानें, क्या है समझौते के अंदर

समझौते के बारे में जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समझौता असम में रहने वाले बोडो आदिवासियों को कुछ राजनीतिक अधिकार और समुदाय के लिए कुछ आर्थिक पैकेज मुहैया कराएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखी जाएगी तथा एनडीएफबी की अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख मांग नहीं मांगी गई है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि समझौता राज्य के विभाजन के बिना संविधान की रूपरेखा के अंदर किया गया है।

चौथे राज्य बंगाल में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास

सीएम ममता ने कहा- केवल अल्पसंख्यक नहीं, सभी का है प्रदर्शन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कोलकाता। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल अब चौथा राज्य बन गया है, जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है।

विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की योजनाओं को निरस्त करने की अपील की गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, यह प्रदर्शन केवल अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि सभी का है। इस आंदोलन का सामने से नेतृत्व करने के लिए मैं हिंदू भाइयों का धन्यवाद करती हूं।

बंगाल में हुई हिंसा

गौरतलब है कि गत 20 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जाएगा। बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस, राज्य में कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। पिछले महीने कानून पारित होने के बाद राज्य में हिंसा और तोड़-फोड़ भी हुई थी।

तकरार का मुद्दा बना सीएए

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थो चटर्जी ने सदन में दोपहर करीब दो बजे यह प्रस्ताव पेश किया, जो कि पास हो गया। तीन राज्य- केरल, राजस्थान और पंजाब - नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पहले ही पास कर चुके हैं। यह कानून राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच तकरार का नया मुद्दा बन कर उभरा है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस इस विवादित कानून का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे लागू करने पर जोर दे रही है।

पश्चिम बंगाल में हम सीएए, एनआरसी, एनपीआर को नहीं लागू होने देंगे। हम शांतिपूर्वक लड़ाई जारी रखेंगे।

कोई फांसी पर लटक रहा हो उससे अरजेंट कुछ नहीं: सीजेआई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी है। इस खौफ में जी रहे दोषियों में एक मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करे। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मांग पर उसे रजिस्ट्री जाने का सुझाव दिया है। खुद चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने माना कि मुकेश की याचिका पर त्वरित सुनवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को 1 फरवरी को फांसी पर चढ़ाया जाना है तो उसकी याचिका पर सुनवाई पहली प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया बलात्कार मामले के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका 17 जनवरी को खारिज कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजे जाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी।

निर्भया रेप केस

बारी-बारी से दया याचिका दाखिल कर सकते हैं

कहा जा रहा है कि इन तीनों में कोई एक 31 जनवरी तक दया याचिका दाखिल कर देगा। उसके बाद बाकी दो भी बारी-बारी से दया याचिका दाखिल कर सकते हैं ताकि फांसी को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए टाला जा सके। निर्भया के माता-पिता भी यही आशंका जताते हुए निराशा प्रकट कर चुके हैं।

16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुई इस खौफनाक घटना के एक अन्य दोषी विनय शर्मा की माफी याचिका भी राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, लेकिन उसने बाद में यह कहते हुए अर्जी वापस ले ली थी कि इसके लिए उसकी राय नहीं ली गई थी। उसने अब तक राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं दी है। वहीं, दो अन्य दोषियों अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता के पास भी राष्ट्रपति से क्षमा दान की गुहार लगाने का विकल्प बचा है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

अफजल से प्यार, सामी से परहेज क्यों

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान में जन्मे भारतीय नागरिक और सिंगर अदनान सामी को पदम श्री दिए जाने को लेकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सामी की मां नौरीन खान भारतीय हैं और जम्मू से हैं।

उन्होंने कांग्रेस पर जम्मू-कश्मीर

सामी को पदम श्री पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

की मुस्लिम महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि कांग्रेस को याकूब मेमन, अफजल गुरु जैसे देशद्रोहियों से दिक्कत नहीं है लेकिन अच्छे मुसलमानों से दिक्कत है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस, आप और लिबरल्स को सिर्फ वैसे ही मुसलमान पसंद हैं जो पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट और सेना को गाली देते हैं। देशद्रोहियों के लिए इकरार और अच्छे मुसलमानों के लिए इनकार।

जो देशद्रोह का काम करे, यासीन मलिक, याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी इन सब के लिए इकरार। जो अच्छे काम करके आगे बढ़े उनके लिए इनकार, ये कैसी बात है?